

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अतारंकित प्रश्न संख्या : 4

21 , 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में सेवानिवृत्ति को आयु

4. श्री नलीन कुमार कटील:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) संवर्ग के संपूर्ण संकाय और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं में सेवानिवृत्ति को आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का कोई निणय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त निणय को सभी सीएचएस संवर्गों और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं में लागू किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ह;

(ग) क्या सरकार को उक्त निणय को लागू करने में हुई अनियमितताओं की जानकारी है और यदि हां, तो उन चिकित्सा सेवाओं और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जहां उक्त निणय को लागू नहीं किया जा रहा है; और

(घ) सरकार द्वारा सभी चिकित्सा सेवाओं में केन्द्रीय और राज्य दोनों को सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे ह?

त

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री श्वे )

(क) से (घ): सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सीएचएस) के शिक्षण उप-संवर्ग के अधिकारियों को सेवानिवृत्ति को आयु 65 वर्ष तक बढ़ाए जाने के लिए 5.6.2008 को निणय लिया था। इसके पश्चात, सरकार ने 31.5.2016 को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों, गैर-शिक्षण और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सेवानिवृत्ति को आयु बढ़ाकर 65 करने का निणय लिया। इसके अलावा, केन्द्रीय चिकित्सा सेवाओं अथात् आयुष चिकित्सकों, सशस्त्र चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत सिविलियन डॉक्टरों, भारतीय आयुध फैक्ट्री स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कायरत दंत चिकित्सकों, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों तथा रेलवे मंत्रालय के तहत दंत चिकित्सकों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम रायफल्स के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारियों के उप-संवर्ग के डॉक्टरों तथा कर्मीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों को सेवानिवृत्ति को आयु भी बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निणय 27.09.2017 को लिया गया था।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निणय राज्य सरकार के चिकित्सकों पर लागू नहीं होते और राज्य सरकार के चिकित्सकों के बारे में ऐसी कोई जानकारी केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जा रही है।

उक्त निणय के कार्यान्वयन में कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

\*\*\*\*